भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
****

मासिक मंत्रिमंडल सारांश अगस्त - 2021

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

i. कोविड – 19 के समाधान के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा:

- मिशन कोविड सुरक्षा - भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन" को डीबीटी के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीआईआरएसी (पीएसयू) द्वारा भारतीय कोविड वैक्सीन विकास में तेजी लाने और वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। मिशन के तहत 5 वैक्सीन कैंडीडेटों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें से 4 उन्नत नैदानिक चरण में हैं और एक उन्नत पूर्व नैदानिक चरण में है। प्रमुख विशेषताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
  - डीबीटी-बीआईआरएसी समर्थित जायकोव-डी, दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन, जिसे जायडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है, को 20 अगस्त, 2021 को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार (ईयूए) प्राप्त हुआ।
  - डीबीटी-बीआईआरएसी समर्थित देश की पहली एमआरएनए-आधारित वैक्सीन, जिसे जेनोवा द्वारा सुरक्षित पाया गया, को 24 अगस्त, 2021 को सुरक्षा डाटा के आधार पर भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा चरण II/III परीक्षण के लिए अनुमति दी गई।
  - बायोलॉजिकल ई ने सहायक-प्रोटीन सबयूनिट आधारित वैक्सीन कैंडीडेट पर सुरक्षा और प्रतिरक्षाजनकता की दृष्टि से अपना चरण II/III अध्ययन शुरू कर दिया है।
  - भारत बायोटेक द्वारा इंट्रानेजल (अंत: नासिका) वैक्सीन कैंडीडेट के लिए द्वितीय चरण का परीक्षण शुरू किया गया है।
- साथ ही, मिशन के तहत अखिल भारतीय 19 नैदानिक परीक्षण स्थलों, प्रतिरक्षाजनकता जांच के लिए 3 सुविधाओं और मॉडल पशु चुनौती को पूरा करने के लिए 3 सुविधाओं का समर्थन किया जा रहा है।
- कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 03 उपक्रमों (पीएसयू) की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। भारत बायोटेक से 03 सार्वजनिक उपक्रमों [हैफकिन बायोफार्मा, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल)] और गुजरात कोविड वैक्सीन कंसोर्टियम (जीसीवीसी) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जा रहा है और नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है।

- आईआईएल से बीबीआईएल को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है और औषधि पदार्थ के 03 बैचों को औषधि उत्पादन के लिए बीबीआईएल को सौंप दिया गया है।
- जीसीवीसी, हैफकिन और बिबकॉल के लिए टर्म शीट और सुविधा डिज़ाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

- विभाग ने 27 अगस्त 2021 को आयोजित कोविड-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समिति (वीईसी) की 12वीं बैठक में मिशन कोविड सुरक्षा की मध्यावधि समीक्षा की सुविधा प्रदान की।

ख. वैक्सीन परीक्षण की सुविधा की स्थापना *(वीटीएफ):*

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद को 17 अगस्त, 2021 को वैक्सीन के परीक्षण और बैच जारी करने के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) के रूप में अधिसूचित किया गया है। डीबीटी वैक्सीन विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस), पुणे को 28 जून, 2021 को सीडीएल प्रयोगशाला के रूप में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

ग. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठकें (एनटीएजीआई):

- विभाग ने 12 अगस्त, 2021 को टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के कोविड-19 कार्यकारी समूह की 28 वीं बैठक में भाग लिया, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की परस्परता और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित मुद्दों; परिणामों की नीति और कार्यक्रम निहितार्थ; स्पुतनिक वैक्सीन और उत्पाद शामिल करने पर अद्यतन रूप से विचार-विमर्श किया गया।
- विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू वैक्सीन स्वीकृति के वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 16 अगस्त, 2021 को एनटीएजीआई के टीकाकरण और वैक्सीन अनुसंधान और क्षमता निर्माण (एसडब्ल्यूजी-आईवीआरसीबी), जनसंख्या आधारित कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा निगरानी के भारतीय नेटवर्क पर प्रोटोकॉल के बारे में स्थायी कार्य समूह की 7वीं बैठक में विधिवत रूप से भाग लिया।

घ. क्वाड की बैठकें*:*

- विभाग ने 03 अगस्त 2021 को विदेश मंत्रालय (एमईए) की जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया, जिसमें डीबीटी को जेबीआईसी के भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को समर्थन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया।
- विभाग ने 13 अगस्त, 2021 को आयोजित 'सीईपीआई के 100 दिवसीय वैक्सीन विकास लक्ष्य' के लिए क्वाड सहयोग के अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी/विभागीय बैठक में भी विधिवत रूप से भाग लिया।
- विभाग ने क्वाड सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 18 अगस्त 2021 को क्वाड विशेषज्ञों की पहली बैठक में विधिवत रूप में भाग लिया।

- विभाग ने 24 अगस्त, 2021 को वैक्सीन वितरण, सामंजस्य और प्रशासन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उप-समूह की तीसरी बैठक में भाग लिया, जिसमें आपातकालीन स्थितियों में डोज के वितरण और समर्थन पर क्राड समन्वय से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

ड. भारतीय सार्स-कोव-2 जीनामिकी कंसोर्टियम *(आईएनएससीओजी)*

भारतीय **सार्स-कोव-2** जीनोमिकी कंसोर्टियम (**आईएनएससीओजी**) की स्थापना डीबीटी, डीएसटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीएसआईआर, शिक्षा मंत्रालय, आईसीएमआर और राज्य सरकारों की 28 + 7 नई आईजीएसएल जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं के एक समूह के साथ एक अंतर-मंत्रालयी पहल के रूप में की गई थी जो समस्त देश में सार्स-कोव-2 वायरस के पूरे जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने का एक समग्र उद्देश्य, वायरस के प्रसार और उसके विकास के बारे में समझने में हमारी सहायता करता है।

30 अगस्त 2021 तक, आईएनएसएसीओजी ने 70,420 सार्स-कोव-2 जीनोम का अनुक्रम किया है। इनमें से 51,651 नमूनों का विश्लेषण किया गया है और पैंगोलिन वंश वर्गीकरण दिया गया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसका सहसंबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को प्रस्तुत किया गया है।

आईएनएसएसीओजी नेटवर्क में प्रयोगशालाओं को 10 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया है और इस प्रकार जीनोम अनुक्रमण क्षमता को बढ़ाया गया है। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एनसीडीसी द्वारा अद्यतन किया जाता है ताकि अनुक्रमित किए जाने वाले नमूनों की संख्या के साथ-साथ अस्पतालों से नमूनों की रिपोर्टिंग और अनुक्रमण करने और समुदाय में फैले कोविड-19 को समझने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण के रूप में सीवरेज निगरानी के द्वारा जीनोम अनुक्रमण की गति में तेजी लाई जा सके।

च. परीक्षण/नैदानिकी

देशभर के सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण को बढ़ाने के लिए हब तथा स्पोक मॉडल में शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। अभी तक कोविड परीक्षण के लिए 21 शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टरों की स्थापना की गई है और 59.60 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।

इसके अलावा ग्रामीण भारत में परीक्षण की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण हेतु आई-लैब (संक्रामक रोग प्रयोगशाला)- मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की गई। पहली प्रयोगशाला को टीएचएसटीआई हब के साथ जोड़ा गया है और फरीदाबाद क्षेत्र में इसने अब तक **25084 परीक्षण** पूरे करे लिए हैं।

ii. माननीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 अगस्त, 2021 को स्वदेशी गायों के जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए एक चिप (इंडिगाऊ) जारी की है।

माननीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 अगस्त, 2021 को स्वदेशी गायों के जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए चिप (इंडिगाऊ) जारी की है जो पहली अकेली न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोरफिजम (एसएनपी) आधारित चिप है जो स्वदेशी गायों की नस्लों जैसे गिर, कॉकेरेज, साहिवाल, ऑनगोलिटों की शुद्ध नस्लों के संरक्षण के लिए तैयार की गई है। यह स्वदेशी चिप बायोटेक्नोलॉजी विभाग का एक स्वायत्तशासी संस्थान, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएआईबी), हैदराबाद के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई थी। इस अवसर पर डॉ. रेणु स्वरूप, सचिव डीबीटी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएआईबी), हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक और डीबीटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इंडिगॉऊ दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर (एसएनपी) रखे गए हैं जो यूएस तथा यूके की 777k इल्यूमिना चिप से अधिक है। हमारी स्वदेशी गायों की यह चिप आत्म आश्वस्त भारत/"आत्मनिर्भर भारत" की ओर बढ़ते भारत का एक प्रमुख उदाहरण है। यह चिप हमारी अपनी उत्तम विशेषताओं वाली नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकारी योजनाओं के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी होंगी जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दो गुणा बढ़ा देगी।

iii. जैवसुरक्षा

(i) विभाग ने **05.08.2020** और **19.08.2020** को आनुवांशिक फेरबदल समीक्षा समिति (आरसीजीएम) की **212**वीं और **213**वीं बैठकें आयोजित कीं। बैठक के दौरान **212**वीं आरसीजीएम बैठक में **22** आवेदनों पर विचार किया गया, जबकि **213**वीं आरसीजीएम बैठक में **17** आवेदनों पर विचार किया गया। इन अनुप्रयोगों में आयात/निर्यात/स्थानांतरण/प्राप्तियां, सूचना मदें और बायोफार्मा के लिए पूर्व-नैदानिक विषाक्तता अध्ययन, तथा कृषि के लिए आयात/निर्यात/स्थानांतरण/प्राप्तियां शामिल हैं। आरसीजीएम द्वारा प्रत्येक आवेदन पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया गया।

माह के दौरान (**31.08.2021** तक) आईबीकेपी पोर्टल पर **18** संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया।

(ii) 12.08.2021 और 26.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच जैव सुरक्षा जागरूकता के लिए 10वें और 11वें अंत:सक्रियता सत्रों का आयोजन किया गया।

iv. डीजीएफटी मामले:

एससीओएमईटी वस्तुओं (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) के निर्यात की अनुमति मांगते हुए 11 आवेदनों के संबंध में इस विभाग की टिप्पणियां डीजीएफटी को सूचित की गई थी।

v. डीबीटी की सामाजिक पहुंच

क. **आजादी का अमृत महोत्सव:**

विभाग जन भागीदारी के आधार पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। माह के दौरान, विभाग ने "**विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहुंच- जनसाधारण से जुड़ाव**" के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए।

- **छात्र संपर्क**:
  - **क.** शोधकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों के बीच सामंजस्य और बातचीत को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोच तथा वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित करने के लिए **15** विज्ञान सेतु/ओपन डे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  - ख. देश भर में महत्वांकाक्षी जिलों में स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संग्रहालयों की श्रृंखला में मणिपुर के चंदेल जिले में पहले विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।
  - ग. डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों में से एक ने भारतीय विज्ञान की महिमा का जश्न मनाने के लिए प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों डॉ. अमित दत्त, डॉ. ओबैद सिद्दीकी और डॉ. सिद्धेश कामत के जीवन और कार्य पर चार वेबिनार भी आयोजित किए।

- **स्टार्टअप संपर्क**:
  - क. विभाग के पीएसयू (बीआईआरएसी) द्वारा समर्पित बायोनेस्ट इन्क्यूबेटरों ने उद्यमिता चुनौतियों और अवसरों, सतत् नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर कृषि उद्यमिता में अवसर आदि जैसे विषयों के तहत 6 सार्वजनिक आउटरीच वेबिनार भी आयोजित किए।
  - ख. आत्मनिर्भर भारत के लिए डीबीटी समर्थन के साथ विकसित विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करते हुए साप्ताहिक सोशल मीडिया सफलता की कहानियां प्रकाशित की गई।

- **कृषक संपर्क**: विभाग द्वारा समर्थित बायोटेक किसान हब ने 18 जागरूकता और मार्गदर्शन कार्यक्रमों जिन्हें किसान मेला कहा जाता है का नेतृत्व किया। इनमें बीज उपचार और जैव-उर्वरक के मिट्टी के अनुप्रयोग, उच्च मूल्य की गैर-मौसमी सब्जी की संरक्षित खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, आईपीएम और आईएनएम पद्धति आदि जैसे विषयों पर आचार्य एन जी रंगा, कृषि विश्वविद्यालय, गुन्टूर, आंध्रप्रदेश में एक मेगा किसान मेला भी आयोजित किया गया।

- **समाज संपर्क**: डीबीटी- राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीजीबी) द्वारा "बांस शिल्प क्षेत्र में जनजातीय कारीगरों के लिए कौशल और क्षमता निर्माण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया था।

vi. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- इंडो-फिनिश संयुक्त आमंत्रण प्रस्ताव: अन्वेषक गतिशीलता के लिए वित्तपोषण की घोषणा की गई है। आमंत्रण प्रस्ताव **11** अगस्त, **2021** से **23** सितंबर, **2021** तक आवेदन जमा करने के लिए खुला है
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने 19 अगस्त, 2021 और 26 अगस्त, 2021 को क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग समूह पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- द्विपक्षीय सहयोग के तहत जलवायु स्मार्ट कृषि क्षेत्र में भारत-डच सहयोग: डीबीटी, भारत और एनडब्ल्यूओ, नीदरलैंड द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से कृषि पर जलवायु परिवर्तन के (अपेक्षित)

प्रभावों को कम करने के लिए अनुप्रयोग- उन्मुख समाधानों में योगदान करने वाले अनुसंधान पर केंद्रित थीम जलवायु स्मार्ट कृषि पर तीन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं।

vii. प्रकाशन और पेटेंट

माह के दौरान विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 104 शोध प्रकाशन और 8 पेटेंट दायर/प्रदत्त किए गए।

viii. एसएएचएजे (सहज): उपयोग और राजस्व

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने **साइंटिफिक इंफास्ट्रक्चर एक्सेस फॉर हार्नेसिंग एकेडेमिया यूनिवर्सिटी रिसर्च ज्वाइंट** कोलबोरेशन **(सहज)** पोर्टल लांच किया जहां डीबीटी- स्वायत्तशासी संस्थानों और डीबीटी समर्थित अवसंरचना कार्यक्रमों में अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्ट-अप/उद्यमियों को अपने उपकरण और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के साथ साझा भी किया जाता है। माह के दौरान 1,316 उपयोगकर्ताओं ने डीबीटी स्वायत्तशासी संस्थानों में सेवाओं का लाभ उठाया और कुल 1,36,69,818/- रूपये का राजस्व अर्जित किया।

ix. बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान -

विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान देश में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिक विवरण संलग्नक **I** पर उपलब्ध है।

x. बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) :

विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूएस) देश में नवाचार, परिवर्तनीय अनुसंधान, उद्योग, स्टार्टअप उद्यमिता और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अधिक विवरण संलग्नक **II** पर उपलब्ध है।

I. महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट

(i) दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: लागू नहीं

(ii) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों का अनुपालन: लागू नहीं

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	टिप्पणियां
-	-	-

(iii) तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या: शून्य

(iv) ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है: शून्य

(v) ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

सक्रिय फ़ाइलों की कुल संख्या: 14,027	अगस्त, 2021 के दौरान बनाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या: 269

(vi) लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 71	माह के अंत में लंबित लोक शिकायतों की संख्या: 17

(vii) **संचालन और विकास में स्थान और तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदम: शून्य**

(viii) **क. इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है:** यह पुष्टि की जाती है कि मंत्रालय/विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)

ख. एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति: उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में ए.सी.सी. निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं:यह पुष्टि की जाती है कि ए.सी.सी. के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग. उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: 'शून्य'।

(ix) **सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) की स्थिति:**

माह के दौरान जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5,49,070/- रु. की खरीद की गई है।